बिहार • झारखंड • उत्तर प्रदेश • दिल्ली • मध्य प्रदेश • हरियाणा • उत्तराखण्ड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर • हिमाचल प्रदेश • पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

सरकारी आवासों में लगेंगे प्रीपेड मीटर

भुवनेश्वर वात्स्यायन , पटना

सरकारी आवासों में दिन-रात मौज में एसी या फिर सर्दियों में गीजर चला कर पैर धोने का किस्सा व जरूरत नहीं रहने पर भी बिजली का इस्तेमाल अब अतीत की बात होने वाली है। यह भी नहीं चलेगा कि आप का रसूख इस तरह का है कि बिजली बकाये का भुगतान नहीं होने वजह से कट गयी है तो उसे तुरंत जुड़वा लेंगे। बिजली विभाग जल्द ही ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है कि आप जितना पैसा देंगे उतनी ही बिजली जला पाएंगे। पैसा खत्म तो बिजली खत्म। सरकारी आवासों में लगे पुराने बिजली मीटर को हटाकर उनकी जगह संबंधित एजेंसी द्वार प्रीपेड बिजली मीटर लगाये जाएंगे।

क्या है प्री पेड मीटर का तर्क : बिजली के प्री पेड मीटर के संबंध में यह तर्क है कि बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें सरकारी कर्मी बिजली बिल की बड़ी बकाया राशि छोड़कर निकल लेता है। कई मामलों में तो सरकारी आवासों से बिजली बिल नहीं जमा किए जाने की बात भी खूब आती रही है। इससे राजस्व का बड़े स्तर पर नुकसान होता है। प्री पेड बिजली मीटर लग जाने से एडवांस में पैसा मिल जाएगा और फिर बकाये की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।

जितना रिचार्ज, उतनी ही मिलेगी बिजली; राशि खत्म होते ही तत्काल बंद हो जाएगी आपूर्ति

मोबाइल से रिचार्ज करने की भी सुविधा होगी उपलब्ध

चाहें तो कूपन भी मिलेगा, तय दर से थोड़ा कम होगा रेट

जल्द ही शुरू हो जाएगी मीटर लगाने की प्रक्रिया

ऐसी होगी व्यवस्था

सरकारी आवास में रहने वाले अधिकारी या फिर कर्मी को यह तय करना होगा कि एक माह के भीतर वह कितने रुपये बिजली पर खर्च करेगा। राशि बताने पर उसे यूनिट से जोड़ दिया जाएगा। मीटर चेक करने आया कर्मचारी एक कोड के माध्यम से उतनी राशि से प्री पेड मीटर को चार्ज कर देगा। इसके बाद प्री पेड मीटर शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्री पेड बिजली के लिए दी गयी राशि के तहत आवंटित यूनिट पार करेंगे कि बिजली की आपूर्ति स्वत: बंद हो जाएगी। मोबाइल के माध्यम से प्री पेड मीटर के रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध होगी।

> विभाग पहले चरण में सरकारी आवासों में रहने वाले सभी श्रेणी के अधिकारी व कर्मियों को प्रीपेड मीटर की सुविधा उपलब्ध करायेगा। इससे सरकारी आवासों पर बकाये बिजली बिल की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। दिल्ली व उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों में प्री पेड मीटर चलन में आ गया है। इसके लिए हम टेंडर की प्रक्रिया में जा रहे हैं।
>
> ● संदीप पौंड्रिक, ऊर्जा सचिव

प्री पेड मीटर वालों को मिलेगी रियायत : जिन सरकारी आवासों में बिजली का मीटर लगेगा उन्हें बिजली की वर्तमान दर से कुछ कम दर पर बिजली मिलेगी। यह सहूलियत उन्हें एडवांस में पैसा दिए जाने की वजह से मिलेगी।

फायदे

- बिजली कंपनी को सौ फीसदी राजस्व की वसूली होगी
- बिजली बिल जमा कराने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा
- बिल की गलती के कारण दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
- बिजली चोरी पर लगाम, मीटर रीडिंग व बिलिंग की जरूरत नहीं

यह होगी दिक्कत

- मीटर को बार-बार रीचार्ज कराना होगा।
- अचानक रीचार्ज खत्म होने पर आपूर्ति बंद।

मीटर में होगा पूरा रिकॉर्ड

प्रीपेड मीटर में समय-तारीख, डिमांड, पावर फैक्टर, सप्लाई फ्रीक्वेन्सी, वोल्टेज प्रति फेज, स्वीकृत लोड, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट रकम का ब्यौरा होगा।